

शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय किला भवन में प्रवेश मेला का शुभारंभ

छात्राओं को प्रवेश संबंधी जानकारी प्रदान की गई

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय किला भवन में प्राचार्य डॉ. बी. डी. श्रीवास्तव के निर्देशन तथा प्रशासनिक अधिकारी डॉ. वी.पी. बैरागी के मार्गदर्शन में प्रवेश समिति द्वारा नवीन शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश मेला का शुभारंभ किया गया। यह प्रवेश मेला गत दिवस से आगामी 15 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। प्रवेश मेले के उद्घाटन अवसर पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्राओं एवं अभिभावकों का स्वागत करते हुए विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, प्रवेश



प्रक्रिया, विषय चयन, छात्रवृत्ति योजनाओं तथा महाविद्यालय की शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक

गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. बी. डी. श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रवेश मेला छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसरों से जोड़ने तथा उन्हें सही विषय एवं पाठ्यक्रम के

चयन में मार्गदर्शन देने का प्रभावी माध्यम है। प्रवेश संबंधी सभी समस्याओं के समाधान हेतु

महाविद्यालय में सहयता काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहाँ विषय विशेषज्ञ प्राध्यापक एवं कंप्यूटरऑपरेटर्स ने छात्राओं को आवश्यक परामर्श प्रदान कर रहे हैं।

प्रवेश मेले के दौरान छात्राओं को महाविद्यालय की उपलब्धियों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं, एनएसएस, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जा रही है। बड़ी संख्या में छात्राओं एवं अभिभावकों ने मेले में सहभागिता कर प्रवेश प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का आयोजन प्रवेश समिति की संयोजक प्रो. विनीता वर्मा तथा उनकी टीम द्वारा किया गया।

सेफ विलक 2.0 अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर इंदौर पुलिस को मिला प्रदेश स्तरीय सम्मान

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। साइबर अपराधों के प्रति जनजागरूकता फैलाने और डिजिटल सुरक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए चलाए गए 'सेफ विलक 2.0' अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया है। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने इंदौर पुलिस को शौलड एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। यह सम्मान अभियान के दौरान किए गए व्यापक जनजागरूकता प्रयासों और



उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया।

पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में 24 जून से 8 जुलाई 2026 तक संचालित इस अभियान के दौरान इंदौर पुलिस ने साइबर सुरक्षा को जनआंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से शहरभर में अभूतपूर्व स्तर पर जागरूकता गतिविधियां संचालित कीं। स्कूलों, कॉलेजों, कॉलोनियों, बस्तियों, बैंक,

होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमाघरों, प्रमुख मॉल, बाजारों, धार्मिक स्थलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। अभियान के अंतर्गत व्याख्यान, नुकड़ नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, साइबर सुरक्षा गीत एवं नृत्य, रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिताएं, साइबर सुरक्षा रथ, साइकिल रैली, मेराथन, साइबर हैकेथॉन, पोस्टर-बैनर, पंपलेट वितरण तथा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लोक परिवहन वाहनों, सिनेमाघरों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से जागरूकता वीडियो प्रदर्शित किए गए।

पितृ पर्वत मार्ग पर बुढ़निया की 48 एकड़ पहाड़ी पर होगा

1 लाख पौधों का रोपण

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रधानमंत्री के आह्वान पर संचालित 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत इंदौर शहर में वृहद स्तर पर पौधारोपण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पितृ पर्वत मार्ग स्थित बुढ़निया की 48 एकड़ पहाड़ी पर इस वर्ष लगभग 1 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा।

यह पौधारोपण अभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र के विस्तार तथा इंदौर को और अधिक हरित एवं स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अभियान की तैयारियों का लिया जायजा- अभियान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) के कमांडेंट ज्ञानेश्वर खाड़े तथा नगर निगम एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया।

प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीएसएफ अधिकारियों एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ पौधों की उपलब्धता, गड्डे तैयार करने के कार्य, सिंचाई व्यवस्था, पौधों के संरक्षण, रखरखाव तथा पौधारोपण के चरणबद्ध क्रियान्वयन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चर्चा के दौरान मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक तैयारियां समय-सीमा में पूर्ण की जाएं ताकि पौधारोपण अभियान प्रभावी एवं व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके।

महिलाओं और बच्चों की डिजिटल और साइबर सुरक्षा के लिए एनजीओ, महिला आयोग और गूगल एक मंच पर

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। डिजिटल तकनीक के तेजी से बढ़ते उपयोग के साथ महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा आज देश के सामने सबसे बड़ी सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों में शामिल हो गई है। इसी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, आहान फाउंडेशन और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के सहयोग से भोपाल में आयोजित विशेष एनजीओ मीट में डिजिटल सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग पर व्यापक विमर्श हुआ।

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग परिसर में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की सदस्य श्रीमती साधना स्थापक ने कहा कि डिजिटल युग ने जितने अवसर उपलब्ध कराए हैं, उतनी ही नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा केवल कानून या तकनीक का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की



बदलती प्रकृति को देखते हुए डिजिटल जागरूकता, समय पर शिकायत और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार को जन-आंदोलन का स्वरूप देना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग सिखाना समय की आवश्यकता है। परिवार, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों और शासन के समन्वित प्रयासों से ही ऐसा डिजिटल वातावरण बनाया जा सकता है, जहां

प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करें।

कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव श्री सुरेश तोमर भी उपस्थित रहे। 'रिस्पॉन्सिबल नेटिजन' कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित संवाद में महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लेकर जमीनी अनुभव साझा किए तथा डिजिटल सुरक्षा को लेकर सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम में गूगल की डायरेक्टर (सर्च एंड जेनेरेटिव एआई ट्रस्ट एंड सेफ्टी) सुश्री स्मिथा भारद्वाज ने 'चाइल्ड सेफ्टी एंड एआई' विषय पर कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास बच्चों और समाज के हितों को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। उन्होंने सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन जोखिमों की पहचान और बच्चों के लिए जिम्मेदार डिजिटल वातावरण तैयार करने की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं गूगल के ट्रस्ट एंड सेफ्टी विभाग के श्री समीर ने साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं और सुरक्षा मानकों की जानकारी

साझा की।

आहान फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री सोनाली पाटणकर ने डिजिटल सुरक्षा पर आयोजित विशेष सत्र में साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न, फर्जी लिंक, डेटा सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग से जुड़े व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्षरता आज केवल एक कौशल नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है।

कार्यक्रम के समापन पर सभी सहभागी स्वयंसेवी संस्थाओं ने महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, समावेशी और विश्वासपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि शासन, तकनीकी संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज के सामूहिक प्रयासों से ही साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है तथा डिजिटल भारत के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव रखी जा सकती है।

कचरा बनेगा कमाई का खजाना, वेस्ट से तैयार होंगे उपयोगी उत्पाद; लगेंगी अत्याधुनिक मशीनें

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। घरों और दुकानों से निकलने वाला कचरा अब केवल निस्तारण का विषय नहीं रहेगा, बल्कि उससे उपयोगी और टिकाऊ उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे।

इंदौर की ग्राम पंचायत काली बिब्लोद स्थित ठोस अपशिष्ट

प्रबंधन इकाई में जल्द ही आधुनिक मशीनें स्थापित की जाएंगी, जिनकी मदद से प्लास्टिक एवं अन्य ठोस कचरे को प्रोसेस कर टेबल, कुर्सियां, दरवाजे, खिड़कियां सहित कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाएंगी। इस पहल से जहां कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन होगा, वहीं ग्राम पंचायतों

के लिए आय का नया स्रोत भी विकसित होगा।

काली बिब्लोद स्थित एफएसटीपी (फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट) एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई में कचरे के निपटार के साथ रिसाइकलिंग की योजना तैयार की गई है।बीते माह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल

एवं स्वच्छता विभाग की संयुक्त सचिव ऐश्वर्या सिंह ने इस इकाई का दौरा किया था। उन्होंने प्लांट के संचालन, कचरा संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया तथा प्रस्तावित नई तकनीक और मशीनों की जानकारी लेकर इस पहल को सराहा था। जिला

पंचायत के सीईओ सिद्धार्थ जैन ने उन्हें पूरे स्वच्छता मॉडल और प्रस्तावित नवचारों से अवगत कराया। सीईओ जैन का कहना है कि काली बिब्लोद इकाई में जल्द ही मशीनें लगाई जाएंगी, इसकी प्रक्रिया की राह है।

पर्यावरण संरक्षण की पहल-परियोजना के तहत एल्लोमोरेटर

(डेंसिफायर), इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, प्लास्टिक एक्सट्रूडर और पैलेट्टाइज़र जैसी अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी।

इनके माध्यम से प्लास्टिक कचरे को उपयोगी उत्पादों में बदला जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे के बेहतर प्रबंधन से स्वच्छता के साथ ही पर्यावरण

संरक्षण की पहल भी पूरी होगी।कचरे के पुनः उपयोग से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि पंचायतों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

जैविक कचरे से खाद तैयार-वर्तमान में काली बिब्लोद, रणमत बिब्लोद और सलमपुर ग्राम पंचायतों से प्रतिदिन डोर-टू-डोर

कचरा संग्रहित कर इस इकाई तक पहुंचाया जाता है। यहां जैविक कचरे से खाद तैयार की जाती है, जबकि प्लास्टिक और अन्य ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जाता है। नई मशीनों के शुरू होने के बाद इसी कचरे से उपयोगी फर्नीचर और निर्माण सामग्री तैयार होगी।

ठेकेदार के स्पष्टीकरण से शिकायत का निराकरण स्वीकार नहीं, स्वतंत्र तकनीकी जांच करवाएं केंद्र सरकार- जगदीश अग्रवाल

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पत्रकार एवं समाजसेवी जगदीश अग्रवाल ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के गरोठडुदलावदा (सीतामऊ) खंड पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को अत्यंत गंभीर जनाहिट एवं सड़क सुरक्षा का विषय बताते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री वी. उमाशंकर को विस्तृत प्रतिवेदन भेजकर पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराने की मांग की है।

बीवी अग्रवाल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि उन्होंने पूर्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी को शिकायत भेजकर इस दुर्घटना-प्रभावित खंड की हवाई लेवल

टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन तथा संपूर्ण मार्ग का रोड सेफ्टी ऑडिट कराए जाने का अनुरोध किया था, ताकि दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का वैज्ञानिक एवं तकनीकी परीक्षण कर भविष्य में जनहानि रोकी जा सके। उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक, रतलाम द्वारा भेजे गए उत्तर में स्वतंत्र जांच कराने के स्थान पर उन्हीं एजेंसियों एवं ठेकेदारों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसकी प्रति भेजी गई है, जिनके कार्यों के संबंध में शिकायत की गई थी। उनके अनुसार किसी भी शिकायत में संबंधित पक्ष का स्पष्टीकरण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच का विकल्प नहीं हो सकता।

जगदीश अग्रवाल ने कहा कि शिकायत में उठाए गए किसी भी बिंदु पर स्वतंत्र तकनीकी परीक्षण,

स्थल निरीक्षण, वैज्ञानिक विश्लेषण अथवा रोड सेफ्टी ऑडिट कराए जाने का उल्लेख नहीं है। परियोजना निदेशक द्वारा भेजे गए उत्तर में शिकायत के गुण-दोष के आधार पर कोई तकनीकी अथवा विधिसम्मत निष्कर्ष भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे देश की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना है तथा गरोठडुदलावदा (सीतामऊ) खंड पर लगातार हो रही दुर्घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। ऐसे मामलों में केवल संबंधित एजेंसी के स्पष्टीकरण के आधार पर शिकायत का निराकरण करना जनहित, सड़क सुरक्षा तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता। प्रतिवेदन में उन्होंने मांग की है कि पूरे

प्रकरण की जांच किसी स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय तकनीकी एजेंसी अथवा विशेषज्ञ समिति से कराई जाए, दुर्घटना संभावित स्थलों का विस्तृत रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, स्थल निरीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण कराए जाएं तथा जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक एवं सुरक्षा संबंधी उपाय तत्काल लागू किए जाएं। साथ ही जांच पूर्ण होने तक संबंधित अभिलेखों एवं तकनीकी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने तथा की गई कार्रवाई से उन्हें लिखित रूप से अवगत कराने का भी अनुरोध किया गया है। जगदीश अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था अथवा ठेकेदार को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं के

वास्तविक कारणों का निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक परीक्षण कराकर भविष्य में निर्दोष नागरिकों की जान बचाना तथा एक्सप्रेसवे को अधिक सुरक्षित बनाना है। यदि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तकनीकी जांच कराने के स्थान पर केवल संबंधित एजेंसी के स्पष्टीकरण के आधार पर शिकायत का निराकरण करना जनता के साथ धोखा है। अग्रवाल ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन की रक्षा से जुड़ा राष्ट्रीय दायित्व है। इसलिए इस मामले में पारदर्शी, निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं उत्तरदायी जांच कर आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू किए जाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

2019 की बाढ़ में बहा पुल नहीं बन सका, कमजोरी पर कांग्रेस का अनोखा उद्घाटन, विधायक हरदीप का मुखौटा पहन जताया विरोध

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। गुरुवार को युवक कांग्रेस ने धतूरीया पुलिया निर्माण में हो रही देरी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री हरदीप सिंह ङा का मुखौटा



पहनकर अधूरी पुलिया का प्रतीकात्मक उद्घाटन किया। इस दौरान फीता काटा, नारियल फोड़ा और मिठाई बांटी। प्रदर्शनकारियों ने शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। गौरतलब है कि वर्ष 2019 की बाढ़ में धतुरिया पुल बह गया था, तब से कई टेंडर होने के बाद भी यह पुल अभी तक नहीं बन सका है। विधायक ङा की कमजोरी इसे माना जा रहा है।

सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली धतुरिया पुलिया पिछले सात वर्षों (सन् 2019) से पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और अपनी बदहाली पर आंसू रो रही है। क्षेत्र के विकास दावों की पोल खोलते हुए आज युवक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राघव राज सिंह शक्तावत एवं सीतामऊ ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बरोला के

पहनकर और फीता काटकर पुलिया का संकेतिक उद्घाटन किया। इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए युवक कांग्रेस ने क्षेत्र की जनता की समस्याओं की लगातार हो रही अनदेखी पर सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानियों को उजागर करने वाले इस अनूठे विरोध प्रदर्शन के मौके पर गोविंद सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष हनुमंत सिंह, महेश पाटीदार, सुरेश पाटीदार, श्रवण सेन, गजेंद्र सिंह, दीपू सेन, प्रतीक गिरोटिया, मंगल डपकारा, मांगू भाई, कमलेश पटेल, श्रवण रायका, छत्र सांठन के नेता युवराज सिंह, कपिल सुरावत, दुर्गा शंकर धाकड़, दीपक गेहलोत, लकी सुरावत, सुनील पंवार, कालू भाटी, धीरज दादरिया और ईश्वर मालवीय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नेतृत्व में एक बेहद अनूठा और तीखा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री हरदीप सिंह ङा का मुखौटा पहनकर अनाज, राशन, बर्तन, कपड़े एवं वर्षों की मेहनत से जुटाया गया गृहस्थी का लगभग पूरा सामान नष्ट हो गया। हदसे के बाद परिवार अत्यंत विषम परिस्थितियों में जीवनयापन करने को मजबूर है।

घटना की जानकारी मिलने पर मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसान नेता श्यामलाल जोकचंद ग्राम पामाखेड़ा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढाढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने ग्राम के पटवारी से चर्चा कर शासन द्वारा मिलने वाली राहत राशि की जानकारी ली। चर्चा



में सामने आया कि मकान क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में शासन की ओर से अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपये तक की सहायता का ही प्रावधान है। ऐसे में परिवार को हुए वास्तविक नुकसान की भरपाई केवल सरकारी सहायता से संभव नहीं होने पर जोकचंद ने जनसहयोग अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र की आम

जनता, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों, समाजसेवियों एवं दानदाताओं से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने की अपील की। उनकी अपील का सकारात्मक असर पहले ही दिन देखने को मिला और लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग किया। जनसहयोग अभियान के पहले दिन ही विभिन्न लोगों द्वारा पीड़ित परिवार के खाते में करीब 20 हजार रुपये की सहायता राशि जमा कराई गई। श्यामलाल जोकचंद ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित इस परिवार को समाज के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यथासंभव आर्थिक सहयोग देकर इस गरीब परिवार का उजड़ा हुआ आशियाना फिर से बसाने में अपनी भागीदारी निभाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि समाज की सामूहिक पहल से पीड़ित परिवार को इस कठिन समय से उबरने में बड़ी मदद मिलेगी।

आकांक्षी विकासखंड में बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ बेहतर कार्य करें



रतलाम/ प्रवीण व्यास/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सीईओ जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन ने गुरुवार को आकांक्षी विकासखंड बाजना के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं निर्धारित संकेतकों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, कृषि, पशुपालन सहित विभिन्न विभागों के प्रामीटरवार कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों से प्रत्येक संकेतक की प्रगति की जानकारी लेकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सीईओ सुश्री जैन ने कहा कि आकांक्षी विकासखंड में बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा निर्धारित लक्ष्यों की समय-सीमा में शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि फील्ड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग कर योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाये।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत ने विशेष रूप से शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि विद्यालयों में बच्चों के लिए शिक्षा को अधिक रुचिकर एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए नवाचार किए जाएं। उन्होंने कहा कि विकासखंड की फील्ड टीम नियमित रूप से क्षेत्र में भ्रमण कर योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करें।

कलेक्टर ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश

लापरवाही पर उपयंत्री के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा विकास कार्यों की निकायवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर उपयंत्री श्री अंकित मांझी एवं श्री टेकचंद बुनकर के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आगामी माह तक जिले के 1,500 पात्र हितग्राहियों को ऋा वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक एवं नगरीय निकाय आपसी समन्वय से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने तथा पूर्ण आवासों की जियो-टैगिंग निष्पत्ति समय-सीमा में कराने के निर्देश भी दिए गए। नगर परिषद डीकेन में

निर्मित वाटर बॉडी के कार्य में सक्षम स्वीकृत के बिना भुगतान किए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित प्रकरण की जांच के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने निकायों में संचालित निर्माण कार्यों का नियमित स्थल निरीक्षण करें तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करें। वर्षा ऋतु को देखते हुए उन्होंने जर्जर एवं खतरनाक भवनों का सर्वेक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा जनहानि की आशंका वाले भवनों को तत्काल खाली कराने एवं आवश्यकतानुसार ध्वस्त करने के निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में परियोजना अधिकारी डूड्डा एवं डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्रसिंह धावें, नीमच की मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती दुर्गा बामनिया तथा जिले के समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने प्राचार्यों एवं संकुल प्राचार्यों की समीक्षा बैठक लेकर दिए आवश्यक निर्देश

शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षा परिणाम सुधार पर करें विशेष फोकस - कलेक्टर श्री चंद्रा

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला पंचायत सभाकक्ष, नीमच में जिले के सभी प्राचार्यों एवं संकुल प्राचार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम तथा विद्यालयों के संचालन की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले के 105 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की टीम गठित कर जांच कराई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित हो रहे हैं। जांच कर 15 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

उन्होंने सभी प्राचार्यों को समय पर



पाठ्यक्रम पूर्ण कराने, नियमित मासिक परीक्षण, विद्यार्थियों की ग्रेडिंग, काउंसलिंग एवं आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गणित एवं अंग्रेजी विषयों पर विशेष फोकस करने तथा इन विषयों के शिक्षकों का डाइट में पांच

दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की काउंसलिंग एवं गतिविधियों का पृथक रजिस्टर संधारित किया जाए। उन्होंने प्राचार्यों को निर्देशित किया कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षकों की अनावश्यक अनुपस्थिति पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि अपार आईडी का कार्य विशेष अभियान चलाकर 15 दिवस में

पूर्ण किया जाए। जिले के सांदीपनि विद्यालय, उल्कृष्ट विद्यालय एवं पीएम श्री विद्यालयों में चेत कलम प्रारंभ किए जाएं तथा प्रार्थना सभा के साथ योग एवं मेडिटेशन का नियमित आयोजन कराने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय समय में शिक्षकों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में उल्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को 15 अगस्त के अवसर पर सम्मानित करने की जानकारी भी दी गई। इस दौरान विद्यालयों में किए गए नवाचारों की भी समीक्षा की गई।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमन वैष्णव, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती ऐश्वर्या मूंढड़ा, डीपीसी श्री दिलीप व्यास सहित जिले के सभी प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य उपस्थित रहे।

महिला की मृत्यु पर प्रदर्शन, लापरवाही के साथ खून गलत चढ़ाने का भी आरोप, क्लीनिक पर कार्रवाई की मांग

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर की नई आबादी स्थित स्पर्श मंदर एंड चाइल्ड केयर क्लीनिक के बाहर गुरुवार सुबह प्रसूता की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजन शव लेकर क्लीनिक पहुंचे और डॉक्टर पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाने में लगी रही।

रतलाम जिले के बोरवनी निवासी 26 वर्षीय पूजा कुंवर का उपचार डॉ. रोशनी जैन के क्लीनिक पर चल रहा था। परिजनों के अनुसार, 24 जून को उन्हें मंदसौर के अनुयोग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 25 जून को ऑपरेशन के जरिए उन्होंने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। महिला की हालत गंभीर होने पर 26 जून को उन्हें अहमदाबाद रेफर किया गया। वहां 8 जुलाई तक उनका उपचार चला, लेकिन बुधवार रात इलाज के दौरान उनकी

मौत हो गई। गुरुवार सुबह परिजन शव लेकर स्पर्श मंदर एंड चाइल्ड केयर क्लीनिक पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि महिला को गंभीर स्थिति को देखते हुए समय पर रेफर नहीं किया गया। उनका यह भी दावा है कि उपचार के दौरान चढ़ाए गए ब्लड में थक्के (क्लॉट) होने की जानकारी अहमदाबाद के डॉक्टरों ने दी थी, जिससे महिला की हालत और बिगड़ गई। महिला की मौत के मामले में परिजनों

का रोना रोना अंचल के वरिष्ठ पत्रकार व कांग्रेस के सक्रिय नेता एमडी मंसूरी के बड़े पिताश्री वयोवृद्ध जनाब ख्वाजा हुसैन मंसूरी का अल्प,बीमारी के बाद 8 जुलाई रात्रि बुधवार को 80 वर्ष की आयु में इंतकाल हो गया। जिनका,अंतिम जनाजा व मयत गुरुवार सुबह 10-00 बजे निज,आवास से निकाली गई जो बस स्टैंड कब्रिस्तान पर मुस्लिम समाज जनों द्वारा नमाज अदा,कर आपके पुत्र,

कमरुद्दीन,मंसूरी, पीह मंसूरी पत्रकार,एम,डी मंसूरी, खलील हुसैन मकसूद हुसैन,अल्लाफ हुसैन के दादाजी आदि द्वा,महरूम को सुपुर्द खवाक किया गया। जनाब ख्वाजा हुसैन,के निधन से समाज सहित आसपास के क्षेत्र में गहरा दुख हुआ है। आपके नैकियों और यादों को हमेशा सजोकर रखा जाएगा।

ख्वाजा हुसैन धार्मिक ईमानदार, कर्तव्य निष्ठ, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व के नेक दिल,ईसान थे। आपके इस अंतिम सफर में बड़ी संख्या में समाज सहित हजारों सलीम भाई मंसूरी हाजी कदीर बख्श मंसूरी, चांद मोहम्मद मंसूरी, शकूर मोहम्मद मंसूरी, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मनीष जैन,जुलिफकार भुट्टो नारू मोहम्मद मंसूरी,फ़ख़रुद्दीन मंसूरी मोहम्मद हुसैन मंसूरी, फ़ालाल धाकड़, ललित धाकड़, भेरूलाल राठौर कमलेश सुथार, लादू लाल माली गोवर्धन लाल माली,आदि कई गणमान्य नागरिक उपस्थित महरूम के लिए अल्लाह से मेहरम की,मग़फ़िरत फरमाए उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकान सर्वोच्च स्थान दे महरूम के घर वालों को सबरे जमील अता फरमाए यह कामना के साथ अंतिम यात्रा में उपस्थित सभी लोगों द्वारा मेहरूम को,खिराजे अकीदत पेश की पेश कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

अखबारों की रद्दी एवं अनुपयोगी सामग्री की नीलामी हेतु दरें आमंत्रित

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला जनसंपर्क कार्यालय, नीमच द्वारा पुराने समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, समाचार कतरने में बड़ी तबला अनुपयोगी सामग्री, जिसमें लकड़ी एवं लोहे की कुर्सियां, लकड़ी की बड़ी टेबल, गोदरेज टाइपराइटर, ड्यूलि कैमिंग मशीन एवं सैमसंग टीवी शामिल हैं, की नीलामी 17 जुलाई 2026 को की जाएगी।

ई-विकास प्रणाली से पारदर्शी तरीके से हो रहा उर्वरक वितरण

रतलाम/ प्रवीण व्यास/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में किसानों को उर्वरकों का वितरण ई-विकास प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। इस प्रणाली में फसल के रकबे एवं प्रकार के अनुसार कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसा के आधार पर उर्वरक की मात्रा निर्धारित की जाती है, जिससे किसानों को संतुलित पोषक तत्वों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

उप संचालक कृषि विभाग ने बताया कि फसलों के बेहतर विकास के लिए नत्रजन (यूरिया) के साथ फॉस्फेटिक उर्वरकों जैसे सुपर फॉस्फेट, एन.पी.के., डी.ए.पी. तथा पोटाश का संतुलित उपयोग आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ई-टोकन प्रणाली के तहत यूरिया क्रय करने के साथ सुपर फॉस्फेट, एन.पी.के. अथवा डी.ए.पी. में से किसी एक फॉस्फेटिक उर्वरक का चयन अनिवार्य किया गया है।

उन्होंने बताया कि जिले के सभी विकासखंडों में सुपर फॉस्फेट एवं एन.पी.के. उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वर्तमान में जिले में 10,463 मीट्रिक टन यूरिया, 5,850 मीट्रिक टन सुपर फॉस्फेट तथा 6,721 मीट्रिक टन एन.पी.के. का भंडारण उपलब्ध है, जिससे किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल यूरिया पर निर्भर न रहें, बल्कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाकर फॉस्फेटिक उर्वरकों का भी उपयोग करें। इससे फसल की वृद्धि एवं उत्पादन में वृद्धि होती है, जबकि केवल यूरिया के अत्यधिक उपयोग से फसलों में कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है।

सम्पादकीय कनेक्टेटेड कारों पर बढ़ा साइबर हमलों का खतरा

हैकिंग की एक हालिया घटना के बाद चीनी मूल के तीन स्मार्टफोन ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया। इसने वाहन उद्योग की साइबर सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित किया है। बीएटी-बीएमएस, लॉसिजी और इंपॉच-आई-ऑयन नामक इन ऐप्स को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के बैटरी प्रबंधन के लिए बनाया गया था लेकिन उनका दुरुपयोग करके वाहनों को दूर से निष्क्रिय किया जा सकता है। जैसा कि इस समाचार पत्र ने भी रिपोर्ट किया, इस खबर के बाद केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल और उनके कलपुर्जा निर्माताओं से कनेक्टेट कारों और ईवी में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर और उपकरणों की जांच करने को कहा।

कनेक्टेटेड वाहन वे होते हैं जो इंटरनेट से सीधे या स्मार्टफोन से ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़े होते हैं। साइबर सुरक्षा के बिना ऑटोमोबाइल गंभीर सुरक्षा कमजोरियों के शिकार हो सकते हैं और हैकर्स कम से कम एक दशक से ऐसे बग प्रदर्शित करते आ रहे हैं। पीडब्ल्यूएन2ओडब्ल्यूएन ऑटोमोटिव एक ऐसा वैश्विक वार्षिक साइबर सुरक्षा कार्यक्रम है जो वाहनों में कमजोरियों को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है। जनवरी 2026 में, सुरक्षा शोधकर्ताओं ने इस आयोजन के पहले दिन विभिन्न वाहनों में 37 ऐसी कमजोरियाँ प्रदर्शित करने के बाद 5,16,500 डॉलर कमाए जो पहले ज्ञात नहीं थीं।

कनेक्टेटेड कारों को हैकिंग के जरिये ट्रैक और हार्डनैक किया जा सकता है। जैसे इंप्रोटेन्मेंट सिस्टम, वायरलेस चाबियां या निर्माताओं के क्लाउड सर्वर को हैक करके। यहां तक कि टायर प्रेशर जैसे सेंसरों का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक मसौदा अधिसूचना में कनेक्टेटेड वाहनों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से चरणबद्ध तरीके से साइबर सुरक्षा मानकों को लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है।

एआईएस 189 (ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 189) का साइबर सुरक्षा ढांचा संयुक्त राष्ट्र के आर155 विनियमन पर आधारित है जिसे यूरोपीय संघ ने 2022 में लागू किया था। चीन और कोरिया ने हाल ही में ऐसे ढांचे पेश किए हैं। एआईएस189 के तहत किसी भी नए वाहन को तय साइबर सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा। साइबर सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करना नए वाहनों को सड़क पर उतारने की पूर्व-शर्त होगी। अक्टूबर 2027 तक नए मॉडलों के लिए एआईएस189 अनुपालन अनिवार्य होगा। अक्टूबर 2028 तक यह सभी नए यात्री वाहनों पर लागू होगा। इससे पुराने मॉडलों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को उन्नत बनाने और उनमें व्यापक बदलाव करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

रिमोट ऑटो सेवाएं काफी आम हैं। कई वाहन रिमोट ऐप फंक्शन प्रदान करते हैं जिन्से वाहन को गर्म करने, उसमें हवा का प्रवाह तय करने और वातायुन्यूलन व्यवस्था को नियंत्रित करने जैसे काम किए जा सकते हैं। ईवी में रिमोट बैटरी प्रबंधन की सुविधा होती है। ब्लूटूथ में किसी तरह की संध या कमजोरी 10-15 मीटर के दायरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति को वाहन पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकती ?हे। हालांकि सरकारी परामर्श कनेक्टेटेड वाहनों पर केंद्रित है, लेकिन हर आधुनिक वाहन साइबर सुरक्षा चिंताओं को प्रस्तुत करता है। सभी वाहन डेटा एकत्र करने के लिए कई सेंसरों का उपयोग करते हैं और उनमें हैंड्स-फ्री माइक्रोफोन और बाहरी कैमरे लगे होते हैं।

आधुनिक वाहन को एक मोबाइल कंप्यूटर के रूप में देखना व्यावहारिक है। निर्माताओं को डायनोस्टिक डेटा की निगरानी करने और सेवा तथा ओवरहॉल मानकों में सुधार करने की सुविधा देने के अलावा मेमरी में संग्रहीत डेटा चालक की यात्रा आदतों के बारे में बहुत कुछ बताता है और महत्वपूर्ण गोपनीयता चिंताएं प्रस्तुत करता है। डिजिटल सुरक्षा स्थापित करने में एक जटिलता यह है कि कनेक्टेटेड वाहनों में मानकीकरण का अभाव है। कई निर्माता स्वयं के कनेक्टेटेड वाहन इकोसिस्टम बनाते हैं जो वे खुद या तकनीकी साझेदारों के साथ विकसित करते हैं।

इन प्रणालियों का ऑडिट करना सामान्य स्मार्टफोन या पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में कठिन है क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर बहुत अलग-अलग हो सकते हैं। भारत में उपभोक्ता-उन्मुख डिजिटल वाहन सेवाओं ने विभिन्न सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीक विकसित की है। इन प्रत्येक प्रणालियों में कमजोरियां हो सकती हैं और खामियों को दूर करना कठिन हो सकता है। वाहन साइबर सुरक्षा संभवतः नियामकों, सुरक्षा विशेषज्ञों और दुर्घटनापार्ण तत्वों के बीच एक दौड़ बन सकती है। इसलिए एआईएस 189 का कार्यान्वयन एक शुरुआत होगी।

गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का सहज मार्ग है सहजयोग



गृहस्थ धर्म का विवेकपूर्ण पालन ही सहजयोग का वास्तविक स्वरूप है। योग का वास्तविक अर्थ है जुड़ना, मिलना या एकत्व की अवस्था को प्राप्त करना। यद्यपि समय के साथ अनेक प्रकार की योग पद्धतियाँ प्रचलित हुईं, किन्तु प्रत्येक योग का मूल उद्देश्य मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना तथा आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि

से देखें तो प्रकृति का प्रत्येक अणु और परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। उसी प्रकार मनुष्य भी पंचमहाभूतों से निर्मित होने के कारण पूर्णता की खोज में रहता है। उसकी यह खोज तभी पूर्ण होती है जब वह अपने भीतर स्थित आत्मतत्त्व का अनुभव करता है और परम चेतना से उसका योग स्थापित होता है। आत्मज्ञान, आत्मविस्तार और आत्मसाक्षात्कार तब पहुँचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, किन्तु सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही है—असत्य से सत्य की ओर, अधंकार से प्रकाश की ओर तथा सीमित चेतना से असीम चेतना की ओर अग्रसर होना। अनेक आध्यात्मिक मार्ग सांसारिक जीवन से विरक्त की प्रेरणा देते हैं, जबकि सहजयोग यह सिखाता है कि गृहस्थ जीवन का त्याग किए बिना भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। भारतीय संस्कृति में गृहस्थ आश्रम को जीवन का आधार माना गया है और गृहस्थ धर्म का विवेकपूर्ण, संतुलित तथा मर्यादित पालन ही सहजयोग का वास्तविक स्वरूप है। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा प्रदत्त सहजयोग आत्मसाक्षात्कार की ऐसी सहज, सरल और सर्वसुलभ पद्धति है, जिसमें साधना का आरंभ वहीं से होता है जहाँ तक पहुँचने के लिए अन्य साधकों को वर्षों के कठिन तप या अनेक जन्मों की साधना करनी पड़ सकती है। श्री माताजी की कृपा से आत्मसाक्षात्कार के माध्यम से साधक क्षणभर में परम चैतन्य से जुड़ने का अनुभव कर सकता है। इस मार्ग में तो गृहस्थ जीवन का त्याग आवश्यक है, न किसी संबंध या भौतिक वस्तु का परित्याग और न ही किसी प्रकार का आर्थिक शुल्क। आवश्यक है केवल निर्मल हृदय, पूर्ण समर्पण और नियमित साधना। आत्मसाक्षात्कार के बाद प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल कुछ मिनट निर्विचार ध्यान में स्थित रहकर अपनी आध्यात्मिक चेतना को सुदृढ़ बनाए रखना सहजयोग का महत्वपूर्ण अंग है। सहजयोग हमें अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या तथा दुर्वयसनों का त्याग करना सिखाता है, जबकि प्रेम, करुणा, संतोष, क्षमा और आनंद जैसे सद्गुणों को जीवन में स्थापित करता है। यही कारण है कि सहजयोगी वही बन सकता है जो अपने पारिवारिक दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए प्रेमपूर्ण, संतुलित, आनंदमय और संतुष्ट जीवन व्यतीत करे। सहजयोग पूर्णतया निःशुल्क है।

फलैश फलड से पहले फलैशबैक एक गलती, पूरी कहानी खत्म

प्रकृति जब रौद्र रूप धारण करती है, तब मनुष्य की सारी शक्ति क्षणभर में प्रभावहीन हो जाती है। मानसून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही वर्षा भारत के खेतों में जीवन भरती है, तो कभी भीषण बाढ़ और भूस्खलन बनकर गाँव, सड़कें, पुल और अनगिनत जिंग्रियों को लील लेती है। उफनती नदियाँ, विकराल झरने और शांत पहाड़ियाँ पलभर में मौत का मंजर बन जाती हैं। ऐसे समय सबसे अधिक चिंता उन युवाओं की होती है, जो रोमांच के नाम पर जोखिम को ही साहस समझ बैठते हैं। याद रखिए, आप केवल अपने परिवार की उम्मीद नहीं, बल्कि राष्ट्र की अमूल्य शक्ति हैं। इसलिए मानसून के इन तीन-चार महीनों में उफनती नदियों, झरनों, खतरनाक पहाड़ी क्षेत्रों और जोखिमभरे ट्रैकिंग मार्गों से पूरी तरह दूर रहना ही सच्ची समझदारी है।

मानसून की खूबसूरती जितनी मोहक दिखती है, उसका खतरा उतना ही गंभीर होता है। भारत के हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और उत्तर-पूर्व के पर्वतीय इलाकों में हर वर्ष भारी वर्षा, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन तबाही मचाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, इन आपदाओं में हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। मौसम विभाग (आईएमडी) लगातार चेतावनियाँ जारी करता है, फिर भी कई युवा रोमांच के आकर्षण में उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मुम्बई-लीह मार्ग, हरिश्चंद्रगढ़, हरिहर किला, केदारनाथ सहित अनेक पर्वतीय क्षेत्र मानसून में बेहद जोखिमभरे हो जाते हैं।

सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता का सवाल

देश की शिक्षा इस समय हर स्तर पर दो खंडों में बंट गई है, सरकारी और निजी। सरकार के पास संसाधन नहीं हैं, अतः उसे शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना ही है। समाज के जिस वर्ग को शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है, वह सरकारी स्कूलों पर निर्भर है। इसको वह अपनी मजबूरी में ही स्वीकार कर रहा है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता और साख आज सवालों के घेरे में है। सरकारी तंत्र में नियमित सेवा में नियुक्त और हर साधन संपन्न व्यक्ति अपने बच्चों को सामान्य सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों में भेजना पसंद कर रहा है। यहां दो वर्ग बन गए हैं।

सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रतिस्पर्धा इतनी कठिन हो चुकी है कि उसके लिए कोचिंग संस्थानों में जाना जरूरी है। कोचिंग एक शुद्ध व्यापार है। यहां जिन परिस्थितियों में सर्वेदनशील आयु के युवा आते हैं, रहते और पढ़ते हैं, वे अस्वीकार्य स्तर का तनाव, चिंता और चक्कराहट उत्पन्न करती हैं। कक्षा 11-12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी होती है। यदि उन्हें न्यूनतम अंक नहीं मिलें तो आगे की प्रतियोगी परीक्षा में बैठ नहीं सकेंगे। फिर उन्हें मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य व्यावसायिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, कोचिंग में भागीदारी और वहां लगभग प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा में आगे रहने का दायित्व उठाना पड़ता है। इस सबके साथ उन पर माता-पिता की अपेक्षाओं और आशाओं का लगातार बढ़ता दबाव भी है। दूसरी ओर समाज में नैतिकता के प्रति लगातार बढ़ रही शिथिलता और व्यवस्था में कर्तव्यनिष्ठा की कमी ने पेपर-लोक का ऐसा जाल रच दिया है, जिसका कोई समाधान सामने नहीं आ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुछ नकल और पर्चा-लोक में भागीदार माफिया दशकों से इसमें संलग्न हैं और सरकारी तंत्र तथा न्याय व्यवस्था की खिल्ली उड़ा रहे हैं। किसी को भी विश्वास नहीं है कि भविष्य में सरकारी व्यवस्था नियमों का पालन करवा सकेगी। सायाटो इतनी सशक्त है कि उसे तोड़ पाना सामान्य व्यक्ति को असंभव लगता है। नकल माफिया, साल्वर गैंग, पर्चा-लोक इत्यादि सभी शिक्षित लोगों द्वारा ही चलाए और निर्देशित किए जाते हैं। इन समस्याओं का त्वरित समाधान खोजना आवश्यक है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की साख पुनः स्थापित करने के लिए दीर्घकालीन उपाय खोजने होंगे। यह तभी संभव है जब उन परिस्थितियों को ईमानदारी से विश्लेषित किया जाए, जिसके कारण कर्तव्यनिष्ठा में गिरावट आई और नैतिकता केवल पुस्तकों में सिमट कर रह गई।

सर्विधान निर्माताओं ने 14 वर्ष तक के हर बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने के निर्देश दिए थे। यदि प्रारंभ से ही सभी सरकारों ने इस जिम्मेदारी को निभाया होता, सभी बच्चों को शिक्षा का एक समान अवसर देने की भावना को व्यावहारिक स्वरूप दिया होता, अपना उत्तरदायित्व स्वीकार होता और उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए होते, हर वर्ग और आर्थिक स्थिति के बच्चे एक स्कूल में और साथ-साथ पढ़ते तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। सरकारें यदि ऐसा करतीं तो समाज स्वयं आगे आता।

—**डॉ. सुधाकर आशावादी**

गीली चट्टानों पर एक छोटी-सी चूक या ऊपरी पहाड़ों में हड़ बाריश से आया अचानक सेलाब संधलने का मौका तक नहीं देता। जो स्थान कुछ देर पहले सुरक्षित दिखता है, रोमांच पर मौत का रास्ता बन सकता है।

वैधा का वास्तविक अर्थ जोखिम मोल लेना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। आज ट्रैकिंग युवाओं के बीच पर्यटन से बढ़कर एक फैशन बन गई है। सोशल मीडिया की आकर्षक तस्वीरें और वीडियो देखकर अनेक लोग यह भूल जाते हैं कि प्रकृति का सुंदर चेहरा पलभर में भयावह रूप भी धारण कर सकता है। फ्लैश फ्लड, फिनलन भरी चढ़ाईयाँ, उफनती नदियाँ और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में अनावश्यक साहस दिखाना उपलब्धि नहीं, लापरवाही है। कई बार रेड अलर्ट और मौसम विभाग की चेतावनियों के बावजूद लोग जोखिम उठाते हैं। इसका परिणाम केवल एक हादसा नहीं होता, बल्कि पूरा परिवार जीवनभर के दुःख और पीड़ा का बोझ उठاتا है। इसलिए सच्ची बहादुरी प्रकृति को चुनौती देने में नहीं, उसकी चेतावनियों का सम्मान कर सुरक्षित रहने में है।

हर रोमांचक मॉजूल से पहले अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय है। युवाओं को समझना होगा कि जीवन किसी एक ट्रेक, यात्रा या वायरल वीडियो से कहीं अधिक मूल्यवान है। माता-पिता अपने बच्चों में अपने वर्षों के त्याग, संघर्ष और अनगिनत सपनों का भविष्य देखते हैं। एक क्षण की लापरवाही उन सभी उम्मीदों को हमेशा के लिए तोड़

सुरक्षित भोजन के लिए कड़े मानकों की जरूरत, एंटीबायोटिक और कीटनाशक पर सख्त निगरानी जरूरी

मैं यहां कुछ खास विषयों पर चर्चा करना चाहती हूं। सबसे पहले, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण नीतियां बाहरी उपभोक्ताओं के दबाव में क्यों बनाई जाती हैं? एंटीबायोटिक प्रतिरोध एक खामोश महामारी है और हम जानते हैं कि भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है। एक देश के तौर पर हम जीवन रक्षक दवाओं के बेअसर होने से पड़ने वाले स्वास्थ्य बोझ को नहीं झेल सकते इसलिए सरकार दुग्ध एवं मांस सहित अन्य उत्पाद देने वाले मवेशी में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल रोकने के लिए कदम उठा रही है।

वर्ष 2010 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के एक विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर सरकार ने शहद में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के खिलाफ एक सलाह जारी की की थी। इस सलाह के बाद संबंधित एंटीबायोजंटिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 2019 में सरकार ने खाद्य-उत्पादक जानवरों और जलीय कृषि उत्पादों में कोलिस्टिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी वजह यह थी कि कोलिस्टिन इंसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है और इसका अत्यधिक इस्तेमाल रोकने एवं इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।

इस्के बाद नीति-निर्माता पशु आहार में एंटीबायोटिक पर प्रतिबंध लगाने और अन्य कदमों पर विचार कर रहे थे मगर उन्होंने कोई व्यापक ढांचा नहीं अपनाया। आखिरकार, हमारे निर्यात बाजारों की सुरक्षा की जरूरत ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। अच्छी बात यह है कि ये नियम सिर्फ ईशू (यूरोपीय संघ) को भेजे जाने वाले खाद्य पदार्थों के लिए ही नहीं हैं,बल्कि भारत में बिकने वाले मांस, दूध, अंडे, शहद और मछली पर भी लागू होंगे। इससे हमारी सेहत की रक्षा होगी।

यहां मुद्दा सिर्फ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं है। सवाल जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसकी सुरक्षा से भी जुड़ है। हमें कीटनाशक अवशेषों, खाद्य योजकों और अन्य विषाक्त पदार्थों के लिए कड़े मानकों की जरूरत है। इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना नहीं कि भारत के खाद्य पदार्थ निर्यात के लिए बेहतर हों बल्कि सेहत की रक्षा के लिहाज से भी ऐसा करना आवश्यक है। संयुक्त राज्य खाद्य एवं दवा प्रशासन (यूएसएफडीए) के आयात-अस्वीकृति डेटाबेस पर एक नजर डालने से पता चलता है कि वर्ष 2024-25 में भारत से भेजे

राज्यों की वित्तीय सेहत पर दबाव, केरल-तमिलनाडु के श्वेत पत्र ने राजकोषीय सुधार की जरूरत दिखाई



के वर्षों में 6.41 प्रतिशत हो गया है जो कम वृद्धि को दर्शाता है। इसका मुख्य कारण (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) का प्रदर्शन है। तमिलनाडु का श्वेत पत्र भी इस अनुपात में गिरावट की ओर इशारा करता है। वर्ष 2006-07 में यह 8.94 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था जो वित्त वर्ष 2025-26 में घट कर 5.45 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गया है।

इन श्वेत पत्रों का अध्ययन करने से कुछ सवाल उठते हैं। पहला, क्या पहचानी गई वित्तीय चुनौतियां केवल इन दो राज्यों तक ही सीमित हैं या यह समस्या और भी व्यापक है? दूसरा, क्या इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ठोस विकल्प मौजूद है?

राज्यों के पास राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी के जरिये उपलब्ध वित्तीय गुंजाइश समझने के लिए हम वर्ष 2024-25 तक के जांचे (ऑडिट किए हुए) आंकड़ों और मार्च 2026 (2025-26 के) के कुल मासिक खातों का अवलोकन करते हैं। कोविड-19 महामारी से राजस्व में आई गिरावट की तुलना अपने ही पिछले प्रदर्शन और दूसरे राज्मन राज्यों से करता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले उसके कर राजस्व का अनुपात वर्ष 2015-16 में 6.94 प्रतिशत से घट कर हाल

रूप हर कदम पर खतरे का संकेत देता है। हर वर्ष अनेक परिवार केवल इसलिए अप्रूपणीय क्षति झेलते हैं क्योंकि मौसम की चेतावनियों को हल्के में लिया जाता है और र्दियों, विवेक पर भारी पड़ जाता है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि दुर्घटनाएँ केवल दूसरों के साथ होती हैं। वास्तव में सावधानी केवल स्वयं की सुरक्षा नहीं, परिवार और समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है। जब एक युवा सुरक्षित रहता है, तब उसके साथ माता-पिता की उम्मीदें, परिवार के सपने और राष्ट्र का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। इसलिए मानसून में सतर्क रहना कोई त्याग नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और समझदारी का प्रमाण है।

आज देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है, जिनका जोश विवेक से संचालित हो। आपका जीवन केवल आपका नहीं, बल्कि परिवार की उम्मीदों और राष्ट्र के भविष्य की अमूल्य पूंजी है। पर्वतों पर अवश्य जाएँ, लेकिन सुरक्षित मौसम में। नदियों और झरनों की सुंदरता का आनंद लें, पर उनके उपन को चुनौती न दें। सच्ची बहादुरी जोखिम उठाने में नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेने में है। मानसून बोल जाणा, रास्ते फिर सुरक्षित होंगे और प्रकृति फिर खुले मन से आपका स्वागत करेगी। इसलिए युवा साथियों, इन कुछ महीनों तक धैर्य रखें, सतर्क रहें और अपने जीवन की रक्षा करें। आपकी एक सावधानी केवल आपको ही नहीं, बल्कि आपके परिवार के सपनों और राष्ट्र की आशाओं को भी सुरक्षित रखेगी। यही सच्ची विजय, यही वास्तविक वीरता है।

—**प्रो. आरके जैन**

गए लगभग 2,700 खाद्य पदार्थों की खेप अमेरिका में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। इनमें मसाले, चावल और दालें शामिल थीं जिन्हें अत्यधिक या वर्जित कीटनाशक अवशेषों के कारण रोका गया था।

इससे अगला सवाल उठता है। ये मानक कैसे लागू किए जाएं? आयात करने वाले देशों ने अधिकृत प्रयोगशालाओं और यहां तक कि अपनी सीमाओं पर गुणवत्ता और अवशेषों की जांच के आधार पर निगरानी प्रणालियां विकसित की हैं। ईशू की योजना अपने निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है। इसके लिए वह हर खेप के साथ एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मांग करेगा जिसके खाद्य पदार्थ निर्यात करने वाली कंपनी के बजाय किसी सिकरी एजेंसी द्वारा जारी किया गया हो।

वह निर्यात करने वाले देशों में अंकेक्षण (ऑडिट) और सीमा की औचक जांच भी करेगा। यह तंत्र इस तरह बनाया गया है कि अगर कोई खाद्य वस्तु विश्लेषण जांच में असफल रहती है तो 'रेड बटन' दबाकर भौतिक जांच की संख्या बढ़ा दी जाती है। कई बार असफल होने पर गंभीर नतीजे हो सकते हैं। मगर उस भोजन एवं खाद्य पदार्थों का क्या जो निर्यात नहीं किए जाते हैं? तीसरा सवाल यह है कि किसान एंटीबायोटिक्स या कीटनाशकों और अन्य विषाक्त पदार्थों का उपयोग किए बिना उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? अंततः यह केवल एक नियामक चुनौती नहीं है और इसके लिए खाद्य उत्पादन के तरीके में बदलाव की आवश्यकता है। किसान तीन उद्देश्यों के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं यानी पशुओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता की कमी या पशुओं की अधिक संख्या के कारण होने वाली बीमारियां रोकने के लिए और फिर बीमारियों के उपचार के लिए।

अब किसानों को एंटीबायोटिक का उपयोग कर नहीं बल्कि पशुओं के प्रजनन और खाद्य उत्पादन की स्थितियों में सुधार कर बीमारियां रोकनी होंगी। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने किसानों के साथ मिलकर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया है और दिखाया है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल घटाना संभव है। यही वह पारस्परिक लाभ है जिसकी हमें आज के दौर में सख्त जरूरत है।

—**धनंजय राजौरा**

2025-26 में पांच ऐसे राज्य रहे। दूसरी तरफ, राजस्व घाटा पूरा करने के लिए राजकोषीय घाटे का 50 प्रतिशत से अधिक इस्तेमाल करने वाले बड़े राज्यों की संख्या वर्ष 2023-24 में चार से बढ़कर वर्ष 2024-25 में छह और 2025-26 में आठ हो गई है।

दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बढ़ते वित्तीय दबाव के ठोस प्रमाण मिल रहे हैं। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता फिर सामने आ गई है। विकल्प हमेशा की तरह राजस्व बढ़ाना या व्यय का पुनर्गठन करना है। इस संदर्भ में दो विचार हो सकते हैं। पहला, उभरते वित्तीय जोखिम की इस व्यापक घटना के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ राज्य लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखने में सक्षम रहे हैं।

ऐसे राज्यों में गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इनमें उच्च आय और मध्यम आय वाले राज्य, खनिज संपदा से भरपूर राज्य और कृषि क्षेत्र पर निर्भर राज्य शामिल हैं। दूसरी ओर हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान राजस्व के मोर्चे पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जहां राजस्व वृद्धि लगभग 10 प्रतिशत या उससे अधिक है। पिछले अनुभव साझा करना उपयोगी हो सकता है।

दूसरा, हालांकि वित्तीय स्थिति संबंधित व्यापक प्रश्नों को उल्लेख श्वेत पत्रों में किया गया है मगर एक उभरती चिंता पर ध्यान नहीं दिया गया है। अर्थव्यवस्था की व्यापक स्थितियां कुछ चिंताएं पैदा कर रही हैं जिनमें सबसे प्रमुख है पर्याप्त संख्या में उत्पादक रोजगार सृजन की चुनौती। तकनीकी बदलाव इस चुनौती को और भी गंभीर बना सकता है। इस संदर्भ में कल्याणकारी कार्यक्रमाों के विस्तार के पथ में नीतिगत बदलाव अग्रणी है।

इनमें आय प्रूक, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क बिजली और परिवहन के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं।

बदनावर में जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम, रथयात्रा का पहला निमंत्रण दिया चिंतामन गणेश और बैजनाथ महादेव को

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर में भगवान श्री जगन्नाथ जी की आगामी भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में बुधवार शाम को संस्था सृजन के सदस्यों ने किला मैदान स्थित श्री चिंतामन गणेश महाराज एवं श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान को निमंत्रण पत्र अर्पित किया। सदस्यों ने भगवान को मिठाई का भोग लगाया और रथ यात्रा के सफल व निर्विघ्न आयोजन के लिए प्रार्थना की। इस दौरान संस्था के धर्मद अग्निहोत्री,

महेश पाटीदार, पोपसिंह राठौर एवं मनीष शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। इससे पूर्व श्री बैजनाथ महादेव मंदिर परिसर में नगर के विभिन्न सामाजिक एवं

15 साल की उम्र में रखा अपराध की दुनिया में कदम, 27 साल की उम्र तक 19 से ज्यादा केस



जिले के जौन थाना क्षेत्र के ग्राम गमेशपुरा का निवासी है और करीब 8 वर्षों से फरार था। पुलिस के अनुसार, सुनील पर राजस्थान, मध्यप्रदेश और एनसीबी में 19 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें एनडीपीएस एक्ट, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी सहित कई गंभीर अपराध शामिल हैं। राजस्थान पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपये, जबकि मध्यप्रदेश पुलिस ने भी इनाम घोषित कर रखा था। जांच में सामने आया कि सुनील ने 15 वर्ष की उम्र में तस्करों की गाड़ियों की एक्कोर्टिंग से अपराध की दुनिया में कदम रखा था। बाद में उसने खुद बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी शुरू कर दी और राजस्थान-मध्यप्रदेश में मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया। वह तस्करी के दौरान पुलिस की घेराबंदी होने पर कई बार पुलिस पर फायरिंग कर फरार भी हो चुका है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अपने घर के बजाय घने जंगलों में ठिकाना बदल-बदलकर रहता था। पत्नी के जरिए जंगल में ही भोजन और जरूरी सामान मंगवाता था। ANTF ने करीब 15 दिनों तक चक्काहे के वेश में गुप्त निगरानी की और तकनीकी इनपुट के आधार पर उसके ठिकाने की पुष्टि की। बारिश का फायदा उठाते हुए टीम ने देर रात घर की घेराबंदी की। तलाशी के दौरान आरोपी रजाई ओढ़कर छिपा मिला। शुरुआती पूछताछ में उसने झूठी पहचान बताती की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ में अपनी असली पहचान स्वीकार कर ली।

बंद ऋतु में मत्स्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 125 किलो मछली जब्त

राजगढ़/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में बंद ऋतु के दौरान अवैध मत्स्याखेट पर रोक लगाने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा सघन अभियान चलाते हुए गत दिवस को विभिन्न नदी-नालों एवं वृहद जलाशयों में छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान लगभग 50 किलोग्राम प्रतिबंधित थाई, मांगुर मछली जब्त की गई, जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण गड्ढा खोदकर दफन कर विनाश कर दिया गया। वहीं, अलग-अलग स्थानों से 75 किलोग्राम मेजर कपाट मछली भी लावारिस अवस्था में जब्त की गई, जिसे स्थानीय स्तर पर नीलाम कर 5 हजार रुपये की राशि शासकीय खजाने में जमा कराई गई। कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मत्स्य निरीक्षक श्री दिनेश कुमार वंदेरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने लीमाचौहान, सारंगपुर, पंचौर, ब्यावरा एवं राजगढ़ क्षेत्र के जलाशयों तथा नदी-नालों का निरीक्षण किया। टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही अवैध मत्स्याखेट में संलिप्त लोग मौके पर पकड़ी गई मछलियां छोड़कर फरार हो गए। विभाग ने जब्त मछलियों की नियमानुसार कार्रवाई करते हुए नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण की। सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि शासन द्वारा मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है।

नीमच में लंबित मांगों पर पटवारियों ने खोला मोर्चा, सरकार को अल्टीमेटम

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। वर्षों से लंबित मांगों की अनदेखी से नाराज मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया । मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को जापन सोपते हुए संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर पदोन्नति कैडर रिव्यू और अन्य लंबित मांगों पर अगर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 15 से 17 जुलाई तक प्रदेश भर के पटवारी सामुहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके बाद आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और आ़ किया जाएगा।

संघ का कहना है कि लगातार आश्वासन के बावजूद मांगों पर कार्यवाही नहीं होने से पटवारी संवर्ग में भारी असंतोष है ।ओर अब कर्मचारी निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार है ।

पटवारी संघ ने इन मांगों को लेकर उठाई आवाज-संघ ने नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा शीघ्र आयोजित कराने, लंबित मानदेय का भुगतान कराने,जज प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में पटवारी संवर्ग को शामिल करने तथा स्थांतरण नीति के विपरित किये तबादलों को निरस्त करने की मांग उठाई साथ ही जिले से बहार स्थांतरित किये गए सभी पटवारीयो को तत्काल कार्य मुक्त करने की मांग उठाई

सामुहिक अवकाश को लेकर दी चेतावनी- पटवारी संघ ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समयवधि में मांगो का निराकरण नहीं हुआ तो 15 से 17 जुलाई तक प्रदेशभर के पटवारी सामुहिक अवकाश लेकर सांकेतिक



विरोध दर्ज करायेगे,इसके बाद आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से व्यापक रूप दिया जाएगा।

कैडर रिव्यु को शीघ्र लागू कर वेतनमान विसंगतियों का समाधान करे-पटवारी संघ ने जापन में कहा कि प्रदेश के अधिकांश विभागों में नियमित रूप से

पदोन्नति की प्रक्रिया संचालित हो रही है । जबकि पटवारी संवर्ग लंबे समय से इससे वंचित है । जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष व्याप्त है। संघ ने मांग की है कि कैडर रिव्यू लागू कर वेतनमान विसंगतियों का शीघ्र समाधान किया जाए। जब तक कैडर रिव्यू लागू नहीं होता तब तक पटवारियों की पदोन्नति तथा समययान वेतन का लाभ प्रदान किया जाए।

आश्वासन के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं होने से आक्रोश - संघ द्वारा जापन में कहा वर्षों से इन मांगो को लेकर शासन स्तर पर लगातार जापन और प्रतिनिधिमंडल दिये जा रहे है । लेकिन बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया इससे पटवारी संवर्ग में लगातार निराशा एवं असंतोष बढ़ रहा है ।

समय रहते निर्णय नहीं तो करेंगे आंदोलन- संघ ने कहा कि पटवारी संवर्ग अपनी न्यायोचित मांगो के समाधान की अपेक्षा शासन से कर रहा है अगर समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन की समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

दैनिक मालवा हेराल्ड

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर के माथुर कालोनी स्थित महाराणा प्रताप राजपूत धर्मशाला से संलग्न गार्डन में शहीद सूबेदार रविंद्र सिंह राठौर की 25 वीं पुण्यतिथि रजक जयंती के रूप प्रतिभा पर माल्यार्पण कर ट्रस्ट द्वारा मनाई गई श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी राष्ट्रभक्ति और सेवा समर्पण जिसमें शहीद रविंद्र सिंह राठौर ने 9 जुलाई 2001 को जम्मू कश्मीर के सुरनकोट तहसील के जंगलों में सेना के ऑपरेशन रक्षक का नेतृत्व कर आतंकियों के मुकाबले में तीन आतंकियों को मार गिराकर वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद राठौर का जन्म धार जिले के बदनावर तहसील के छोटे से गांव पाना में राठौर परिवार में हुआ था। रविंद्र सिंह राठौर बचपन से ही देश सेवा के प्रति उत्सुक रहे एवं सेना में भर्ती होने के लिए



निरंतर प्रयास करते रहे। आप 1 जनवरी 1979 को पेरा रेजीमेंट में चयनित होकर बैंगलोर से प्रशिक्षण प्राप्त कर अगरा में पदस्थ हुए। आप सेना में सिपाही , लांस नायक, नायक, हवलदार सूबेदार एवं नायब सूबेदार के पद पर सेवारत रहे।

चौहान ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दे व श ी य न ी एकादशी जो शनिवार 25 जुलाई को आ रही है, उस दिन दोपहर 1२00 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी को छपन भोग अर्पित किया जाएगा। इसके बाद कपूर आरती के साथ भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। भगवान श्री जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र एवं माता सुभद्रा सुसज्जित रथ पर विराजमान

होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जिसे श्रद्धालु अपने हाथों से खींचेंगे। रथ यात्रा की शुरुआत दुर्गा चौक स्थित श्री पंडरीनाथ मंदिर से होगी। इसके बाद यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचेगी। जहां श्री बैजनाथ मंदिर परिसर में हरि-हर मिलन का दिव्य और अलौकिक आयोजन होगा। यात्रा के समापन पर महाप्रभु की महाआरती की जाएगी और सभी श्रद्धालुओं को फरियाली खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जाएगा।

आयोजन को लेकर नगर के युवाओं और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह का माहौल है। रथ यात्रा की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभालने के लिए विभिन्न समितियां बनाकर जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जो पूरी निष्ठा से तैयारियों में जुट गई हैं।

प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे,तो वीरता बाँझ हो जाएगी

यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे,तो वीरता बाँझ हो जाएगी



आपके अदम्य साहस को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा बल एनएसजी कमांडो में 8 वर्ष सेवा का अवसर मिला। आप देश सेवा करते हुए 9 जुलाई 2001 को शहीद हो हुए।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम में महाराणा प्रताप ट्रस्ट के संरक्षक जी पी सिंह राठौर, ट्रस्ट अध्यक्ष अंतर सिंह पवार, युवा राजपूत संगठन अध्यक्ष पोपसिंह राठौर(पप्पी बना), नगर परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह पंवार (फूट्वा बापू), भगवान सिंह राठौर,कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह पवार, सरपंच प्रतिनिधि विजय सिंह पवार ,बापू सिंह यादव, मनोहर सिंह पवार ,दिलीप सिंह चौहान ,महियाल सिंह सोनगरा, हर्षवर्धन सिंह राठौर, राकेश सिंह चौहान, सोहन सिंह जादौन,चित्रंजन सिंह राठौर ,मदन सिंह देवड़ा, अनूप जायसवाल, लोकेंद्र सिंह पवार,डॉ कमल सिंह राठौर आदि समाज जन उपस्थित होकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया।

बड़नगर में राजस्व विभाग की घोर लापरवाही

नक्शा बिगाड़े अफसर, भुगत रहा किसान – करे कोई, भरे कोई का जिंदा उदाहरण



बड़नगर/ महेश सोनगरा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। बड़नगर क्षेत्र में राजस्व विभाग की लापरवाही अन्ध खुलकर सामने आ रही है, जहां विभाग की गलती का सीधा खामियाजा गरीब किसान भुगतने को मजबूर है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि किसान अपनी ही खरीदी हुई जमीन को सीमाएं जानने के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही।

मामला साफ है – किसान अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदता है, सीमांकन के लिए आवेदन करता है, और बदले में उसे सुनने को मिलता है कि नक्शा बिगड़ा हुआ है, सीमांकन नहीं होगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह नक्शा बिगाड़ा किसने? क्या किसान ने, या फिर उन्हीं अधिकारियों ने जिनके जिम्मे रिकॉर्ड सुरक्षित रखना था?

हकीकत यह है कि नक्शों में गड़बड़ी, हेरफेर और त्रुटियां राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर ही गंभीर सवाल खड़े करती हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय अधिकारी सीधे किसान को ही उलझाने में लगे हैं।

ग्राम बालोदा लक्खा का मामला तो इस पूरे सिस्टम की गोल खोल देता है। यहां किसान प्रेम सिंह ने लगभग 17 बिस्वा भूमि खरीदी, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा 32 बिस्वा का बताया जा रहा है। यह अंतर सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की लापरवाही का जीता-जागता सबूत है। सबसे चौकाने वाली बात यह है कि सीमांकन का आदेश होने के बावजूद भी अधिकारी नक्शा त्रुटि का बहाना बनाकर कार्रवाई से बच रहे हैं।

आखिर यह कैसी कार्यप्रणाली है, जहां गलती विभाग

सरकारी योजनाओं से वंचित संत-पुजारी समाज, सुरक्षा और मानदेय बढ़ाने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग

बड़नगर/ महेश सोनगरा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ आम किसानों को मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर, मठ-मंदिरों की भूमि पर खेती का कार्य करने वाले संत-पुजारी आज भी इन सरकारी योजनाओं के लाभ से पूरी तरह वंचित हैं। मंदिर की भूमि पर ई-केवाईसी नहीं होने के कारण पुजारियों को खाद-बीज के टोकन नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उन्हें कृषि कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर अ.भा. संत समिति धर्म समाज पुजारी इकाई द्वारा एक जापन नायब तहसीलदार पुनर्मसिंह बघेल टप्पा खरसौद कलां को सौंपा गया ।

जापन के माध्यम से धर्मसमाज प्रदेश अध्यक्ष सालगरामदास ने बताया कि जिस प्रकार आम किसानों की फार्मर आईडी बनी हुई है, उसी तर्ज पर शासन द्वारा संचालित मंदिरों के पुजारियों की भी किसान फार्मर आईडी बनाई जाए। साथ ही उन्हें सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनाकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाया जाए।

पुजारियों का कहना है कि देवस्थानों के पुजारियों की समस्याओं के निराकरण और प्रशासन से बेहतर तालमेल के लिए अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा वर्ष में कम से कम



दो बार बैठक ली जानी चाहिए। इससे पूरे मध्य प्रदेश के संत-पुजारी अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करा सकेंगे, वहीं प्रशासन के पास भी मठ-मंदिरों की संघर्षियों की सही और अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहेगी।

पुजारी समाज ने चिंता जताते हुए कहा कि वर्तमान में लगभग 75 प्रतिशत मंदिरों की जमीनों पर भू-माफियाओं और पड़ोसियों द्वारा अवैध कब्जे कर लिए गए हैं, जिससे मंदिर की जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं। इसके अलावा, पुजारियों को मिलने वाला वर्तमान मानदेय एक दिहाड़ी मजदूरी से भी कम है। मांग की गई है कि इस मानदेय को कलेक्टर रेट के अनुसार किया जाए, ताकि पुजारी सम्मानपूर्वक भगवान की पूजा-अर्चना के साथ अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। इसके लिए राजस्व अभिलेख (खसरा-खतौनी) में पुजारी का नाम दर्ज किया जाना बेहद जरूरी है।

जिले में अब तक 228.38 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

आलोट/ राकेश चौहान/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में इस वर्ष अब तक औसतन 228.38 मि.मी. वर्षा दर्ज की गयी है। जबकि पिछले 24 घंटों में रतलाम जिले में 3.00 मिमी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 2.4 घंटों में आलोट में 0.00 मि.मी., जावरा में 1.0 मि.मी., ताल में 0.0 मि.मी., पिपलोदा में 8.0 मि.मी., बाजना में 3.0 मि.मी., रतलाम में 4.0 मि.मी., रावटी में 4.0 मि.मी. एवं सैलाना में 4.0 मि.मी., वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। विगत 1 जून से अब तक वर्षाभाषक केन्द्र आलोट में 281.0 मि.मी., जावरा में 217.0 मि.मी., ताल में 196.0 मि.मी., पिपलोदा में 264.0 मि.मी., बाजना में 154.0 मि.मी., रतलाम में 329.0 मि.मी., रावटी में 174.0 मि.मी. एवं सैलाना में 212.0 मि.मी., वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है।

विकास को रफ्तार: विधायक श्री पंड्या ने किया 1 करोड़ 70 लाख के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण बदलेगी क्षेत्र की



विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण लोकप्रिय विधायक माननीय जितेन्द्र उदयसिंह पण्ड्या के मुख्य आतिथ्य में किया गया।

इस अवसर पर विधायक श्री पण्ड्या ने कहा कि आज का दिन हमारे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। भूमि पूजन व लोकार्पण के ये कार्य सिर्फ पत्थर लगाना नहीं बल्कि क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। जनता ने जिस वि्वास के साथ मुझे चुना है उस पर खरा उतरना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है क्षेत्र का चहुंमुखी विकास और अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना मेरी प्राथमिकता है। विधायक श्री पण्ड्या ने कहा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ और समय सीमा के भीतर पूरे किए जाए ताकि जनता को इसका जल्द से जल्द लाभ मिल सके।

इस भूमि पूजन एवं लोकार्पण के अवसर पर, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उमरावसिंह जनपद पंचायत उपाध्यक्ष अजब सिंह, खरसोद कला, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजयराजसिंह खरसोद कला, इंगोरिया भाजपा मंडल अध्यक्ष गोपाल आंजना,खरसोद खुर्द मंडल अध्यक्ष मुकेश व्यास ,सरपंच संघ अध्यक्ष मनोहर गुर्जर , गजेन्द्रसिंह राजावत,, श्रीमति सुनीता टीकमसिंह पंवार जनपद सदस्य लखानसिंह , जनपद सदस्य सुखदेव पाटीदार , जनपद सदस्य पुर्व विजयसिंह गोवंधनसिंह पटेल मानियावाद, इन्द्रपालसिंह पण्ड्या पिवराम जाट , भोमसिंह पंवार ,नाथुसिंह जोी सरपंच, राखल चूहेन सरपंच, देवेन्द्रसिंह राणावत सरपंच भेरूलाल सोलंकी सुमेरसिंह ,धर्मेन्द्र सिंह राठौड़ ,भारती चौहान ,देवेन्द्र पटेल के समस्त पंचांग व समस्त ग्रामीणजन उपस्थित थे।

नगर निगम की अपील समिति के सदस्य का निर्वाचन 10 जुलाई को



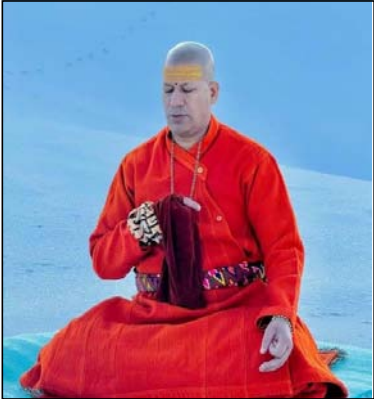
ग्वालियर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर निगम ग्वालियर की अपील समिति के एक सदस्य (अनारक्षित) के निर्वाचन हेतु 10 जुलाई को नगर निगम परिषद सम्मेलन स्थल पर दोपहर 2.30 बजे से निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले समस्त निर्वाचकगण (पार्षदगण) अपनी आईडी (पहचान पत्र) साथ लेकर आयेंगे तथा निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित समस्त निर्वाचकगणों को परिषद हॉल में मोबाइल लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने गुरुवार को दोपहर निगम परिषद कार्यालय पहुंचकर परिषद हॉल का निरीक्षण किया और निर्वाचन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह, अपर कलेक्टर श्री सी बी प्रसाद, अपर कलेक्टर श्री अनिल बनवारिया, एसडीएम श्री अतुल सिंह, अपर आयुक्त नगर निगम श्री प्रदीप तोमर व श्री मुनीष सिकरवार एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने गुरुवार को दोपहर निगम परिषद कार्यालय पहुंचकर परिषद हॉल का निरीक्षण किया और निर्वाचन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह, अपर कलेक्टर श्री सी बी प्रसाद, अपर कलेक्टर श्री अनिल बनवारिया, एसडीएम श्री अतुल सिंह, अपर आयुक्त नगर निगम श्री प्रदीप तोमर व श्री मुनीष सिकरवार एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने नगर निगम की अपील समिति के एक सदस्य के निर्वाचन के संबंध में अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए समय-सीमा में सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंधन किए जायेंगे।

नीमच बनेगा अध्यात्म की राजधानी, 11 जुलाई को स्वामी कैलाशानंद गिरि का ऐतिहासिक नगर आगमन...

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान रखने वाली नीमच नगरी 11 जुलाई 2026 को एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। पहली बार आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज का नगर आगमन होने जा रहा है, जिसे लेकर पूरे मालवा और मेवाड़ अंचल में उत्साह, श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है।

आयोजन को लेकर शहरभर में तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं और इसे नीमच के धार्मिक इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय माना जा रहा है सनातन संस्कृति के संरक्षण, राष्ट्र उत्थान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और विश्व शांति के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस भव्य आध्यात्मिक समामग में देशभर की प्रतिष्ठित संत विभूतियों, जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों और समाजसेवियों की उपस्थिति संभावित है। आयोजन को लेकर प्रशासनिक और



सामाजिक स्तर पर भी व्यापक तैयारियों की जा रही हैं यह दिव्य आयोजन 11 जुलाई 2026, शनिवार को प्रातः 11:15 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक नीमच के दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल में आयोजित होगा। कार्यक्रम में श्रद्धालु आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज के श्रीमुख से प्रवाहित होने वाले आध्यात्मिक संदेश, सनातन विचार और जीवन को नई दिशा देने

वाले प्रेरणादायी वचनों का श्रवण कर सकेंगे एक ही मंच पर जुटेंगी देश की प्रतिष्ठित संत विभूतियां नीमच के धार्मिक इतिहास में यह संभवतः पहला अवसर होगा जब देश की अनेक प्रतिष्ठित संत विभूतियां एक ही मंच से श्रद्धालुओं को आशीर्वाचन प्रदान करेंगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल होने वाले संतों में महंत रवींद्र पुरी जी महाराज अध्यक्ष, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं माँ मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट, हरिद्वार महयोगी बाबा श्री श्री 1008 कालीदास कृष्णानंद जी महाराज बाबा कालीदास धाम, संपला हरियाणा बालमुकुन्दाचार्य जी महाराज पीठाधीश्वर, हातोजधाम एवं विधायक, हवामहल जयपुर महामंडलेश्वर स्वामी मधुसुदानंद गिरि जी महाराज अन्नपूर्णा शक्ति पीठ, सेमलिया धाम इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से केंद्रीय मंत्री, उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, उद्योगपति एवं समाजसेवियों के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है श्रद्धालुओं की सुविधा के

लिए व्यापक तैयारियां आयोजन समिति और प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, बैठक व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।

बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यवस्थाओं का अंतिम रूप दिया जा रहा है आयोजकों का कहना है कि संतों का सानिध्य समाज में सकारात्मक ऊर्जा, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। ऐसे आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते, बल्कि समाज को एक नई दिशा देने वाले प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं चौपड़ा परिवार के अतिथ्य में सजेगा भव्य महामंच इस विराट आध्यात्मिक आयोजन की मेजबानी नीमच के प्रतिष्ठित चौपड़ा परिवार द्वारा की जा रही है। आयोजन को सफल बनाने में विभिन्न सामाजिक संगठनों, धर्मप्रेमी नागरिकों और स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है आयोजन समिति ने इसे केवल

एक परिवार का कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे मालवा-मेवाड़ क्षेत्र की आस्था, संस्कृति और गौरव का महाउत्सव बताया है तथा अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है अनेक राष्ट्रीय हस्तियां प्राप्त कर चुकी हैं आशीर्वाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज देश और विदेश में सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार तथा आध्यात्मिक जागरण के लिए विशेष पहचान रखते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियां समय-समय पर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी हैं नीमच में उनका यह प्रथम आगमन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि यह शहर की सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला अवसर साबित हो सकता है 11 जुलाई को नीमच बनेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का केंद्र, जहां हजारों श्रद्धालु दिव्य संतों के सानिध्य में आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करेंगे।

कलेक्टर ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण



झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने गुरुवार को जिला अस्पताल, झाबुआ का औचक निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध व्यवस्थाओं एवं सुख्खा इंतजामों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की फायर सेफ्टी व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय फायर सेफ्टी सिस्टम की पाइपलाइन में लीकेज पाया गया। इस पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित ठेकेदार को शीघ्र मरम्मत कर लीकेज दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुचारु एवं कार्यशील रहना अत्यंत आवश्यक है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि फायर सेफ्टी सिस्टम की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए तथा आवश्यक सुधार कार्य समय-सीमा में पूर्ण करकर इसकी जानकारी प्रस्तुत की जाए, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों की सुख्खा सुनिश्चित हो सके। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस एल चोपड़ा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेन्द्र भायल एवं अन्य उपस्थित रहे।

13 से 22 जुलाई तक चलेगा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तृतीय चरण

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तृतीय चरण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान की तैयारियों, क्रियान्वयन की रूपरेखा तथा पशुपालकों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तृतीय चरण 13 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य जिले में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना तथा पशुपालकों की आय बढ़ाना है। अभियान के दौरान पशुपालन विभाग का प्रशिक्षित अमला, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, मैत्री गो सेवक एवं दुग्ध संघ के कार्यकर्ता जिले के लगभग 14 हजार पशुपालकों से घर-घर जाकर संपर्क करेंगे। विशेष रूप से ऐसे पशुपालकों को अभियान से जोड़ा जाएगा, जिनके पास तीन से चार गाय अथवा भैंसवशीय मादा पशु हैं। अभियान के दौरान पशुपालकों को पशुपालन के तीन प्रमुख स्तंभ पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार (कृत्रिम गर्भाधान) के संबंध में व्यवहारिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही आधुनिक पशुपालन पद्धतियों, बेहतर प्रबंधन एवं वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपाय भी बताए जाएंगे।कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने बैठक में कहा कि यह अभियान जिले के पशुपालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों को अपनाने से न केवल दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं मैदानी अमले को अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक पात्र पशुपालक तक पहुंचने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि अभियान के दौरान जनप्रतिनिधियों भी गांवों में पहुंचकर पशुपालकों से संवाद करेंगे तथा उन्हें अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। कलेक्टर स्वयं भी जिले के दो ग्रामों का भ्रमण कर पशुपालकों से घर-घर संपर्क कर उन्हें आधुनिक एवं वैज्ञानिक पशुपालन के प्रति जागरूक करेंगे।

कलेक्टर ने किया विकासखण्ड राजपुर का भ्रमण

बडवानी/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्रीमति जयति सिंह ने गुरुवार को विकासखण्ड राजपुर के ग्राम साली, भामपुर एवं सालखेड़ा का भ्रमण किया। इस दौरान कलेक्टर ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल साली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने शिक्षा का गुणवत्ता परीक्षण करने हेतु विद्यार्थियों को अपने समक्ष पढ़वाया साथ ही शिक्षकों को भी यह निर्देशित किया कि वे विषयवार टाईम टेबल बनाकर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दे। शिक्षक केवल ज्ञान का प्रसार नहीं करता, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, चरित्र और भविष्य का निर्माण भी करता है। एक शिक्षक का सबसे बड़ा लक्ष्य विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देना है, जो उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल, संस्कारी और आत्मनिर्भर बनाए। आजीविका भवन भामपुर एवं सालखेड़ा का किया निरीक्षण भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने आजीविका भवन भामपुर एवं सालखेड़ा का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने आजीविका भवन भामपुर में समूह की दीदीयों द्वारा बनाये जा रहे सुदाना पशु पोषण आहार निर्माण के कार्य को भी देखा। समूह की दीदीयों ने कलेक्टर को बताया कि वे 1800 रुपये किंवदल पशु आहार बना रही है। इस पर कलेक्टर ने समूह की दीदीयों से उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार कलेक्टर ने आजीविका भवन सालखेड़ा में समूह की दीदीयों द्वारा संचालित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का भी निरीक्षण कर दीदीयों से दूध की आवक एवं खपत के संबंध में भी चर्चा की। आयुष्मान आरोग्य मंदिर सालखेड़ा का किया निरीक्षण भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने ग्राम सालखेड़ा के आयुष्मान आरोग्य मंदिर का औचक निरीक्षण किया।

दो गायों से शुरू हुआ सफर, आज बनीं लाखों की आय वाली प्रगतिशील गौपालक

आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना ने श्रीमती अर्चना पाटीदार के सपनों को दी नई उड़ान

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। ग्रामीण भारत की असली ताकत उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना में बसती है। जब इन गुणों को शासन की योजनाओं का सहयोग मिल जाता है, तब साधारण किसान भी सफलता का ऐसा इतिहास रच देते हैं, जो पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखंड के ग्राम बावड़ी की श्रीमती अर्चना धर्मेन्द्र पाटीदार इसकी जीवंत मिसाल हैं। कभी केवल दो दुधारू गायों से अपने परिवार की आजीविका चलाने वाली अर्चना आज आधुनिक डेयरी प्रबंधन, वैज्ञानिक पशुपालन और एकीकृत कृषि प्रणाली के माध्यम से प्रतिमाह डेढ़ से दो लाख रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं। 12 सदस्यीय संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियों के बीच वर्ष 2012 में श्रीमती अर्चना ने हरियाणा से दो संकर एचएफ दुधारू गाय खरीदकर डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की। प्रतिदिन लगभग 20 लीटर



दूध का उत्पादन होता था, जिसे साँची दुग्ध संघमि में विक्रय किया जाता था। सीमित आय के कारण परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वर्ष 2022-23 में उन्हें आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना का लाभ प्राप्त हुआ और यहीं से उनके जीवन में बदलाव का नया अध्याय शुरू हुआ।

योजना के अंतर्गत 3.80 लाख रुपये की इकाई लागत पर 95 हजार रुपये का

शासकीय अनुदान प्राप्त हुआ। इस सहायता से उन्होंने हरियाणा से पाँच उन्नत संकर एचएफ गायें खरीदीं। यही वह अवसर था जिसने छोटे डेयरी व्यवसाय को आधुनिक एवं व्यावसायिक डेयरी फार्म में बदलने की मजबूत नींव रखी।

श्रीमती अर्चना ने आधुनिक तकनीकों को अपनाने हुए गायों का सेक्स सॉटेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान कराया, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली मादा बछियाँ का उत्पादन हुआ। आज उनके डेयरी फार्म में लगभग 20 वयस्क दुधारू गायें एवं 20 उन्नत नस्ल की मादा बछियाँ हैं। नियमित देखभाल और वैज्ञानिक प्रबंधन के कारण दूध उत्पादन बढ़कर 180 से 200 लीटर प्रतिदिन तक पहुँच गया है।

पहले पशुओं को केवल भूसा और सामान्य पशु आहार दिया जाता था। अब

साइलेज, सुदाना पशु आहार, मिनरल मिक्सचर तथा पूरे वर्ष नैपियर घास खिलाई जाती है। इस वैज्ञानिक पोषण व्यवस्था से दूध उत्पादन में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई तथा उत्पादन लागत में लगभग 2 रुपये प्रति लीटर की कमी आई।

दूध दोहन के लिए मिल्किंग मशीन के उपयोग ने उनके डेयरी फार्म को नई पहचान दी। इससे दूध की गुणवत्ता बेहतर हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई और पशुओं में थनेला रोग की संभावना भी कम हो गई। आधुनिक तकनीक ने उनके श्रम को भी काफी हद तक आसान बनाया।

ब्रीडर एसोसिएशन की सदस्य के रूप में श्रीमती अर्चना कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली मादा बछियाँ तैयार कर रही हैं। लगभग 45 हजार रुपये की लागत से तैयार होने वाली बछियाँ 14 से 16 माह बाद लगभग 1.50 लाख रुपये तक में विक्रय होती हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होने के साथ

क्रेटेड वाटर का उपयोग खेतों की सिंचाई में किया जाता है, जबकि गोबर से निर्मित बायोगैस से पूरे परिवार का भोजन तैयार होता है। बायोगैस से प्राप्त स्लरी एवं गोबर खाद खेतों में जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग की जाती है। इससे खेती की लागत कम होने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है।

डेयरी व्यवसाय के साथ उन्होंने उद्यानिती विभाग के सहयोग से पॉलीहाउस में टप्पाट एवं मिर्च की पौध तैयार करना तथा खीरा एवं ककड़ी का उत्पादन प्रारंभ किया, जिससे प्रतिवर्ष 6 से 8 लाख रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इसके अलावा मक्का एवं सोयाबीन की खेती भी उनकी आय का मजबूत आधार है।

एक समय ऐसा था जब उनकी मासिक आय लगभग 40 हजार रुपये थी, लेकिन आज विभिन्न कृषि एवं पशुपालन जविधियों से उनकी मासिक आय 1.50 से 2 लाख रुपये तक पहुँच चुकी है। उन्होंने दो स्थानीय युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

स्कूल बसों की जांच कर 49 हजार से अधिक का शमन शुल्क वसूला गया

बडवानी/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला परिवहन अधिकारी, बड़वानी तथा प्रभारी यातायात थाना बड़वानी द्वारा गुरुवार 09 जुलाई को अंजड़ एवं टीकरी में संचालित स्कूल बसों की चौकंग की गयी। चौकंग के दौरान 82 से अधिक स्कूली वाहनों में इमरजेन्सी गेट, बीमा, फिटनेस, पी.यू.सी., परमिट आदि दस्तावेज चेक किये गये तथा 11 वाहनो के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जाकर रु. 49,990 का शमन शुल्क वसूला गया । स्कूल प्रभारियों को वाहनों में जो अनियमितताएँ पायी गयी उनके संबंध में निर्देशित किया गया कि वे सात दिवस में अपनी वाहनों को दुरुस्त करावें एवं दस्तावेजो को पूर्ण करावें। उस निर्देशों का पालन समयाविध में ना किये जाने पर नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाकर दण्डित किया जावेगा ।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति लोहारदा जिला-देवास (म.प्र.)

क्रमांक / मंडी / नि. / 25-26 / 347

लोहारदा विनांक- 06.07.2026

- / / द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना / - /

प्रमुख अभियंता म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त (एकीकृत पंजीयन प्रणाली) पंजीकृत निविदादातारों से प्रतियोग पर आधार पर सिस्टम निविदाएं क्रमांक 2026/MP&AM/519585-1, के अंतर्गत ऑनलाईन निविदाएं **दिनांक 09.07.2026 समय 05.30 से दिनांक 23.07.2026 को साय 5.30 बजे** तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकर्ता को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल <http://www.mptenders.gov.in/nicspg/app> पर प्राप्त होगी, एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल <http://www.mpmmandiboard.gov.in> पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट-आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति, लोहारदा
जिला-देवास (म.प्र.)

भारतवाक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, लोहारदा
जिला-देवास (म.प्र.)

नक : शुभम ताप्रकार (सभी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)

Website:- www.malwaherald.com

दैनिक

मालवा हेराल्ड

उज्जैन, शुक्रवार 10 जुलाई 2026

पेज नं.

8

सीवरेज एजेंसी की लापरवाही : न स्टाफ, न संसाधन, 10 साल बाद भी अधूरा है सीवरेज प्रोजेक्ट

सुरक्षा उपकरणों के बिना सीवर में उतरने को मजबूर कर्मचारी, देशभर में अब तक 1300 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में पिछले करीब 10 वर्षों से सीवरेज लाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन आज तक यह परियोजना पूरी नहीं हो सकी है। इससे शहर के कई क्षेत्रों में लोगों को पेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि सीवरेज लाइन का संचालन और रखरखाव करने वाली एजेंसी के पास न तो पर्याप्त कर्मचारी हैं और न ही जरूरी संसाधन। ऐसे में सीवर और सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, ठेका शर्तों के तहत सीवरेज लाइन शुरू होने के बाद उसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की होती है। इसके लिए नागरिकों से

रेलवे स्टेशन के सामने ऑटो चालक पर चाकू से हमला

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। गुरुवार सुबह रेलवे स्टेशन के सामने ऑटो चालक पर दो लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल चालक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हमला करने वालों की तलाश कर रही है।

बताया जा रहा है कि सेंट पॉल स्कूल के पास विजयनगर में रहने वाला सचिन पिता सुरेंद्र गुप्ता ऑटो चलाता है। रात 2 बजे वह रेलवे स्टेशन पहुंचा था। उसने कुछ सवारी छोड़ी और वापस ट्रेन आने का समय होने पर सुबह 6 बजे के लगभग रेलवे स्टेशन पहुंच गया। इस दौरान सवारी बैठाने की बात को लेकर उसका दो रिक्शा चालकों से विवाद हो गया। दोनों रिक्शा चालकों ने चाकू से ऑटो चालक सचिन पर हमला कर दिया। रेलवे स्टेशन के सामने हुई चाकू बाजी से अफरा तफरी मच गई। चाकू मारने वाले दोनों हमलावर अपनी ऑटो रिक्शा से भाग निकले। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। घायल को चरक अस्पताल ले जाया गया था जहां परिजनों के पहुंचने पर उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवास गेट थाना पुलिस मामले में रेलवे स्टेशन के सामने लगे सीसीटीवी कैमरो के फुटेज देखकर चाकू मारने वालों की पहचान के प्रयास कर रही है। घायल हमलावरों को नहीं पहचानता है।

फायर अफसर से मारपीट के दूसरे दिन होटल पीतांबरी रैजिडेंसी सील कार्रवाई के दौरान परिजनों ने करीब तीन घंटे तक किया विरोध

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। महाकाल क्षेत्र में फायर अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में प्रशासन ने दूसरे ही दिन सख्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार दोपहर होटल पीतांबरी रैजिडेंसी को सील कर दिया। नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम कार्रवाई के लिए होटल पहुंची, जहां होटल संचालक के परिजनों ने करीब तीन घंटे तक विरोध किया। परिजनों ने प्रशासन की कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताते हुए आपत्ति जताई और सीलिंग की कार्रवाई रोकने का प्रयास किया। इस दौरान होटल परिसर में काफी देर तक बहस और हंगामे की स्थिति बनी रही। प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को कार्रवाई का आधार समझाया और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के

पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बाल संरक्षण को लेकर प्राचार्यों का प्रशिक्षण सम्पन्न



उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन, बालकों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम तथा बच्चों को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्यों का एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला उज्जैन श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिला पंचायत उज्जैन के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ एवं उच्च न्यायालय की अधिवक्ता सुश्री सलोनोि बाहेती ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों, अनिवार्य रिपोर्टिंग, पीड़ित बच्चों की गोपनीयता, विशेष न्यायालय की कार्यवाही तथा विद्यालयों की कानूनी जिम्मेदारियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप ंगुड टच-बैड टच की जानकारी देकर जागरूक किया जाना आवश्यक है। साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध की जानकारी प्राप्त होने पर 24 घंटे के भीतर पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सूचना देना अनिवार्य है। सूचना न देने पर दंड का प्रावधान है तथा पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखना भी कानूनन आवश्यक है। उन्होंने विद्यालयों में शिकायत पेटी स्थापित करने, बाल संरक्षण समिति का गठन करने तथा नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर भी बल दिया।

वार्षिक शुल्क भी लिया जाता है। इसके बावजूद एजेंसी अब तक अपना पूरा ऑपरेशन और मेंटेनेंस सिस्टम तैयार नहीं कर सकी है। बताया जा रहा है कि एजेंसी के पास पर्याप्त स्टाफ तक नहीं है। नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई हैं। ऐसे में सीवरेज संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए नगर निगम को ही आगे आना पड़ता है।

शहर में कई स्थानों पर सीवर लाइन का काम अधूरा होने से लोगों को आए दिन पेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी भी लगातार सामने आ रही है। कई बार कर्मचारी बिना गैस मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य सुरक्षा

उपकरणों के ही गहरे सीवर चैंबर में उतर जाते हैं। जबकि सीवर में मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसें जमा हो जाती हैं, जिनसे कुछ ही सेकंड में दम घुट सकता है। हाल ही में पीपली नाका क्षेत्र में ऐसी ही एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतरे कर्मचारियों में एक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। विशेषज्ञों का कहना है कि कई निजी ठेकेदार खर्च बचाने के लिए सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हैं और कर्मचारियों की जान जोखिम में डाल देते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अनुसार, वर्ष 1993 से दिसंबर 2025 तक देशभर में सीवर और सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान

1,313 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि आधुनिक मशीनें उपलब्ध होने के बावजूद कई जगह अब भी कर्मचारियों से सीवर में उतरकर सफाई कराई जाती है। कानून भी बिना सुरक्षा इंतजामों के किसी व्यक्ति को सीवर या सैप्टिक टैंक में उतारने की अनुमति नहीं देता।

विशेषज्ञों का मानना है कि सीवर सफाई में पूरी तरह मशीनों का उपयोग, पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षित स्टाफ और एजेंसियों की जवाबदेही तय किए बिना ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल होगा। शहर में भी सीवरेज परियोजना की धीमी रफ्तार और सुरक्षा व्यवस्था की कमी अब गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है।

जिले के 671 सरकारी स्कूल भवन जर्जर, बारिश में बढ़ा बच्चों की सुरक्षा का खतरा मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन अब तक नहीं मिला बजट

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की बदहाल स्थिति बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। बारिश का दौर शुरू होने के बाद कई स्कूल भवनों की छतों से पानी टपक रहा है, दीवारों का प्लास्टर झड़ रहा है और कई जगह भवन जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद मरम्मत के लिए जरूरी बजट अब तक जारी नहीं हुआ है। ऐसे में हजारों विद्यार्थी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं।

जानकारी के अनुसार, इस वर्ष बारिश शुरू होने से पहले जिले के 671 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के भवनों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। उम्मीद थी कि बारिश से पहले राशि मिल जाएगी और मरम्मत कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन अब तक बजट स्वीकृत नहीं होने से स्कूलों की हालत जस की तस बनी हुई है।

सबसे ज्यादा चिंता 32 ऐसे स्कूलों को लेकर है, जहां भवनों की स्थिति बेहद खराब बताई जा

जंगल में भट्ठी पर कट्ची शराब बनाते आरोपी गिरफ्तार दबिश में 10 लीटर शराब के साथ मिला महुआ लहान, हिरासत में आरोपी

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। नागावां के जंगल में हाथभट्ठी पर कच्ची शराब बनाये जाने की खबर मिलने पर भाटपचलाना थाना पुलिस की टीम ने बुधवार को दबिश मारी। मौके से 10 लीटर शराब से भरी केन के साथ एक हजार किलोग्राम महुआ लहान जप्त किया गया।

इससे उन्हें पढ़ाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों की स्थिति का सर्वे कर प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन बजट नहीं मिलने से मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो सका।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर से राशि स्वीकृत होते ही प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य कराया जाएगा। हालांकि बारिश के मौसम में बजट मिलने की संभावना कम होने से आशंका जताई

शैलेन्द्रसिंह सिसोदिया, आरक्षक जीवन जाट, हितेश निम्बोला, विजय जाट, मुकेश नागर और उदयसिंह यादव के साथ दबिश दी गई। मौके से शराब बनाने वाले श्यामलाल पिता पन्नालाल 34 साल निवासी ग्राम नौगावा को हिरासत में लिया गया। उसने 10 लीटर कच्ची शराब तैयार कर केन में भरकर रखे थी। वहां से शराब बनाने

के लिये रखा एक हजार किलोग्राम महुआ लहान मिला। पुलिस टीम ने भट्ठी को नष्ट कर सभी उपकरण और सामग्री बरामद कर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया है। जिसे गुरुवार को कोर्ट में पेशकर जेल भेजा गया है।

जिले के 671 सरकारी स्कूल भवन जर्जर, बारिश में बढ़ा बच्चों की सुरक्षा का खतरा मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन अब तक नहीं मिला बजट

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की बदहाल स्थिति बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। बारिश का दौर शुरू होने के बाद कई स्कूल भवनों की छतों से पानी टपक रहा है, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और प्लास्टर गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अधिभावक और शिक्षक लंबे समय से इन भवनों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूलों में छात्राओं के लिए पर्याप्त शौचालय सुविधा भी नहीं है।

इससे उन्हें पढ़ाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों की स्थिति का सर्वे कर प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन बजट नहीं मिलने से मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो सका। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर से राशि स्वीकृत होते ही प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य कराया जाएगा। हालांकि बारिश के मौसम में बजट मिलने की संभावना कम होने से आशंका जताई

जिसे गुरुवार को कोर्ट में पेशकर जेल भेजा गया है।

शिपा नदी में गिरे बाइक सवार दंपति, पत्नी की मौत

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। किराए के मकान में रहने वाले पति पत्नी आधी रात को बाइक से लौट रहे थे। त्रिवेणी स्थित छोटी रफ्ट से गुजरते समय दोनों बाइक सहित शिपा नदी में गिर गए। पति को तैरना आता था लेकिन पत्नी के दिव्यांग होने पर वह डूब गई। पति उसे बाहर लेकर आया लेकिन पत्नी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामला जांच में लिया है।

नानाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि बुधवार गुरुवार रात 11ः30 बजे के लगभग सूचना मिली कि त्रिवेणी छोटी रफ्ट से बाइक सहित एक पुरुष और महिला शिपा नदी में गिर गए हैं। पुलिस घटना स्थल पहुंची इस दौरान कुछ लोग दोनों को निकाल कर अस्पताल पहुंच गए थे। जहां सामने आया कि महिला की डूबने से मौत हो चुकी है। युवक की हालत ठीक है। मामले की जांच शुरू की गई इस दौरान सामने आया कि मृतक महिला का नाम रितु है जिसकी उम्र 28 साल है। उसके साथ बाइक पर सवार युवक पति पवन है। दोनों मूल रूप से शाजापुर के कालापौल स्थित ग्राम कोटडी के रहने वाले हैं। वर्तमान में केटीएम शोरूम के पास किराए के मकान में रहते हैं। रितु एक पैर से दिव्यांग थी। पति से पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने प्रेम विवाह किया है रितु सीहोर की रहने वाली थी। दोनों उज्जैन में रहकर प्रार्वेटि जब करते हैं। रात में वह इंदौर रोड स्थित बालाजी ढाबे पर खाना खाने गए थे जहां से वापस लौटते समय उनके साथ हादसा हुआ है। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सामने से आ रहे वाहन से बचने का प्रयास करते समय दोनों बाइक सहित शिपा में गिरे थे फिलहाल मामले में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया गया है। पति और घटना स्थल पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज नागदा में बहुप्रतिक्षित उज्जैन-जावरा 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का भूमि पूजन करेंगे

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार 10 जुलाई को नागदा के श्री ऋषमुक्तेश्वर मंदिर परिसर में बहुप्रतिक्षित उज्जैन-जावरा 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का भूमि पूजन समारोह आयोजित किया जाएगा।

निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दोपहर 2ः00 बजे मुख्यमंत्री डॉ यादव का हेलीपैड, नागदा पर आममन होगा। इसके पश्चात दोपहर 2ः10 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर उनके द्वारा लोकापर्ण/भूमिपूजन एवं हेलेमेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उज्जैन-जावरा फोरलेन ग्रीनफील्ड हाईवे का भूमिपूजन, अस्थायी भवन केंद्रीय विद्यालय, नागदा एवं जनसेवा गृह का शुभारंभ किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 98.730 कि.मी. लंबाई के उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है। यह मार्ग उज्जैन के ग्राम मंगरोला से प्रारंभ होकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (एन.एच.8 लेन इंटर चेंज) से जोड़ते हुए जावरा में होटल-जुबो के समीप समाप्त होगा।

यह 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे होगा, जिसमें पेव्ड शोल्डर्स होंगे। परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर क्रियान्वित किया जाएगा। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति की राशी 5017 करोड़ है, यह परियोजना उज्जैन एवं रतलाम जिलों को लाभांवि्त करेगी तथा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जो की आगामी सिंहस्थ 2028 में विभिन्न शहरों से आने वाले श्रद्धालुओं की कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से उज्जैन को दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर तथा एक्सप्रेसवे से सीधा जोड़कर क्षेत्रीय आर्थिक विकास की गति मिलेगी।

स्टॉप डायरिया सह दस्तक अभियान के अन्तर्गत आयोजित हुई कार्यशाला

राष्ट्र अपना ध्यान की थीम पर आधारित है। इसमें जन्म से पाँच वर्ष तक के बच्चों में गंभीर कुपोषण, एनीमिया, निर्मोहिता, निजलीकरण एवं संक्रमण की पहचान, त्वरित उपचार एवं आवश्यकता अनुसार रेफरल के साथ-साथ विटामिन ए की खुराक दी जाएगी तथा ओ.आर.एस. पैकेट व जिंक टैबलेट का वितरण किया जाएगा।